



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 1983/चैत्र 1, 1905

No. 133]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 1983/CHAITRA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1983

का.आ. 190(द) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हा-
गया है कि कावेरी शुगर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, कावेरी
फैक्टरी जो तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरपल्ली जिले में पेट्राइ-
बेटालैंड में चीनी का विनायण कर रही है और जो अधिसूचित
चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की
मात्रा में कमी न होने देने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में
ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधि-
नियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के
साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 167 (अ), तारीख
25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि
28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी सविश्वाओं,
सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी
उद्देशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो कई और वित्तीय
संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोटोकॉल या

उद्भूत होने वाली सभी वाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका
उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार
है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यवित्त को लागू किए जा सकते
हैं, प्रदर्शन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की ओर अवधि के लिए
निलम्बित रहेगा।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एस. यू.-ए]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd March, 1983

S.O. 190(E).—Whereas the Central Government is satisfied
that in relation to the Cauvery Sugar and Chemicals Limited,
Cauvery Factory, manufacturing sugar at Pettaivayalai in
the district of Tiruchirappalli in the State of Tamil Nadu, being
the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in
the interests of the general public with a view to preventing
the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by
clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of
section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management)
Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the
notification of the Government of India in the Ministry of
Agriculture (Department of Food) No. S.O. 167(E), dated
the 25th March, 1982, the Central Government hereby
declares that the operation of all obligations and liabilities
accruing or arising out of all contracts, assurances of property,
agreements, settlements, awards, standing orders or
other instruments in force immediately before the 28th
March, 1980 (other than those relating to secured liabilities
to banks and financial institutions) to which the said sugar

undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-A]

का.आ. 191(अ) : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि अयोध्या शगर मिल्स, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में राजा का सहसपुर में चौनी का विनियोग कर रही है और जो अधिमूलित चौनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चौनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दीप्ति से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चौनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के लंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 168(अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चौनी उपक्रम या उक्त चौनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चौनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की ओर अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एम. यू.-बी]

S.O. 191(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Ajudhia Sugar Mills, manufacturing sugar at Raja-ka-Sahaspur in the district of Muradabad in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 168(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-B]

का.आ. 192(अ) : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि जीजामाना सहकारी इकाइ कारखाना लिमिटेड, जो महाराष्ट्र राज्य के बन्दाना जिले में शक्कर नगर में चौमी का विनियोग कर रही है और जो अधिमूलित चौनी उपक्रम है, के संबंध में चौनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दीप्ति से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है:

अतः, केन्द्रीय सरकार, चौनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के लंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 169(अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका उक्त चौनी उपक्रम या उक्त चौनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चौनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की ओर अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

[फा. सं. 13-1/83-एन. एम. यू.-सी]

S.O. 192(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Jijamata Sahkari Sakhar Karkhana Limited, manufacturing sugar at Shunkarnagar in the district of Buldana in the State of Maharashtra, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 169(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-C]

का.आ. 193(अ) : केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है राय बहादुर नारायण मिहं शगर मिल्स लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के महाराष्ट्र पर में लक्ष्मर में चौमी का विनियोग कर रही है और जो अधिमूलित चौनी उपक्रम है, के संबंध में चौनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दीप्ति से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चौनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के लंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 170(अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों से संबंधित हैं) से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का, जिनका

उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की ओर अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

[फा. मं. 13-1/83-एन. एस. यू.-डी]

S.O. 193(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Lhaksar in the district of Salsarapur in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 170(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-D]

का. आ. 194(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि श्री सीताराम शगर कम्पनी लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में बैतालपुर में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दिक्षिण से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ प्रतिट उप-धारा (1) के स्पष्ट (स) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (साद्य विभाग) की अधिसूचना न. का. आ. 172 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 29 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी आधिकारियों और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पत्रकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की ओर अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

[फा. मं. 13-1/83-एन. एस. यू.-ई]

S.O. 194(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Shree Sitaram Sugar Company Limited, manufacturing sugar at Baitalpur in the district of Deoria in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 171(E), dated

the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-E]

का. आ. 195(अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि देवरिया चीनी मिल्स लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दिक्षिण से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ प्रतिट उप-धारा (1) के स्पष्ट (स) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (साद्य विभाग) की अधिसूचना न. का. आ. 172 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी आधिकारियों और दायित्वों का, जिनका उक्त चीनी उपक्रम या उक्त चीनी उपक्रम का स्वामी एक पत्रकार है या जो चीनी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 में एक वर्ष की ओर अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

[फा. मं. 13-1/83-एन. एस. यू.-एफ]

S.O. 195(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Deoria Sugar Mill, Limited, manufacturing sugar, at Deoria in the district of Deoria in the State of Uttar Pradesh being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture Department of Food) No. S.O. 172(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83-NSU-F]

का. आ. 196 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सैकमरिया चीनी मिल्स लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गोडा जिले में चीनी का विनिर्माण कर रही है और जो अधिसूचित चीनी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधि-

नियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के साथ पर्छित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 173 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाइ, स्थायी आदेशों या अन्य लिखरों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों में संबंधित हैं) से प्रोटोकूल या उद्भूत होने वाली सभी बाध्याओं और दायित्वों का, जिनका उबड़ चीजी उपक्रम या उबत चीजी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीजी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

[पा. सं. 13-1/83-एन. एम. यू.-जी]

S.O. 196(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Seksaria Seyer Mills Limited, manufacturing sugar at Bahman in the district of Gonda in the State of Uttar Pradesh, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 173(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No 13-1/83 NSU-G]

का. आ. 197 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का यह समाप्त हो गया है कि केशोराय पाटन सहकारी शगर मिल्स लिमिटेड, जो राजस्थान राज्य में बन्दी जिले में केशोराय पाटन में चीजी का विभिन्नण कर रही है और जो अधिसंचित चीजी उपक्रम है, के सम्बन्ध में चीजी उद्योग के उत्पादन की मात्रा में कमी न होने देने की दीप्ति ने सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अब केन्द्रीय सरकार, चीजी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 7 की उप-धारा (2) के गाथ पर्छित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 174 (अ), तारीख 25 मार्च, 1982 के क्रम में यह घोषित करती है कि 28 मार्च, 1980 के ठीक पूर्व प्रवत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति, हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाइ, स्थायी आदेशों या अन्य लिखरों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रत्याभूत दायित्वों में संबंधित हैं) से प्रोटोकूल या उद्भूत होने वाली सभी बाध्याओं और दायित्वों का, जिनका उबड़ चीजी उपक्रम या उबत चीजी उपक्रम का स्वामी एक पक्षकार है या जो चीजी उपक्रम या ऐसे व्यक्ति को लागू किए जा सकते हैं, प्रवर्तन 28 मार्च, 1983 से एक वर्ष की और अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

[पा. सं. 13-1/83-एन. एम. यू.-एच]
पा. आर बनर्जी, संयुक्त सचिव

S.O. 197(E).—Whereas the Central Government is satisfied that in relation to the Shri Keshoraiputan Sahkari Sugar Mills Limited, manufacturing sugar at Keshoraipatan in the district of Bundi in the State of Rajasthan, being the notified sugar undertaking, it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing the fall in the volume of production of the sugar industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 7 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. S.O. 174(E), dated the 25th March, 1982, the Central Government hereby declares that the operation of all obligations and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the 28th March, 1980 (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said sugar undertaking or the person owning the said sugar undertaking is a party, or which may be applicable to the said sugar undertaking or that person, shall remain suspended for a further period of one year from the 28th March, 1983.

[F. No. 13-1/83 NSU-H]
N. R. BANERJEE, Lt. Secy.